महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

देश में किसानों के हितों से जुड़ी अर्थनीति की राजनीति नहीं है -विजय जावंधिया

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान देते किसान नेता विजय जावंधिया। दाएं से प्रो. अनिल के. राय अंकित, मीडियाविद डॉ. संजय बघेल।

वर्धा दि. 17 अगस्त: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विजय जावंधिया ने एक विशेष व्याख्यान में कहा कि देश में किसानों के हितो की अर्थनीति और उससे संबंधीत राजनीति खत्म हो गई हैं। 1980 से 1990 तक एक दशक में किसान आंदोलन की जो चेतना और ताकत थी वह प्रभावहीन हुई हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसानों की समस्या सत्ता परिवर्तन से नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव है।

विजय जावंधिया महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र द्वारा एम. एम., एम. फिल., पी-एच. डी. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्र-छात्राओं से 'किसानों की समस्या एवं मीडिया की भूमिका' विषय पर बातचीत कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रो. अनिल कुमार राय अंकित ने की। कार्यक्रम में मीडियाविद डॉ. संजय बघेल विशेष रूप से उपस्थित थे।

किसान आंदोलन, किसानों की आत्महत्या और उनसे जुड़ी सामाजिक समस्यों पर छात्रों द्वारा पुछे गये सवालों का जवाब देते हुए जावंधिया ने अपने विद्वत्तापूर्ण वक्तत्व से छात्रों को किसानों की समस्या की जडों से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि में खुद एक किसान हूँ और किसानों के दुख-दर्द से जमिनी स्थर पर जुडा हूँ। किसानों को दी जाने वाली सबसिडी से जुड़े सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका में कपास के दाम गिरने पर वहां का किसान आत्महत्या नहीं करता क्योंकि उसे

सरकार द्वारा सबसिडी दी जाती हैं परंतु भारत में ऐसा नहीं होता। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 48 प्रतिशत था वह आज मात्र 12 प्रतिशत रह गया हैं। उन्होंने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्था में बगैर सरकार की सहायता से खेती नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि सिंचित और असिंचित खेतीहर किसानों में भेदभाव किया जाता है, इससे किसानों की सामाजिक समस्याएं और बढ़ गयी हैं। पिछले दिनों सरकार ने 71 हजार करोड़ रूपये के कर्ज माफी की घोषणा की थी जिसमें बाद में संशोधन कर छोटे किसानों के हित में 20 प्रतिशत या 20 हजार रूपये जो भी अधिक होगा उतनी कर्ज माफी का निर्णय लिया गया। परंतु उस पर मीडिया का ध्यान नहीं गया। उन्होंने तर्क दिया कि किसान कर्ज के बोझ से नहीं बल्कि उसे न मिलने वाली सहायता से आत्महत्या कर रहा हैं। उन्होंने माना कि महाराष्ट्र में एकाधिकार कपास खरीद योजना की सफलता किसान आंदोलन की ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो. अनिल राय ने कहा कि काफी दिनों से किसानों से जुडी समस्याओं से छात्रों को रूबरू कराने के लिए विजय जावंधिया को बुलाने की तमन्ना थी वह पूरी हुई है। वास्तव में जिस विदर्भ की भूमि में यह विश्वविद्यालय स्थापित है उस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को इतने विस्तार के साथ जावंधिया के अलावा कोई नहीं बता सकता है। 'जावंधिया और किसान आंदोलन' यह विदर्भ क्षेत्र के लिए एक समीकरण सा बना हुआ है। देश और दुनिया के कई मंचो पर उन्होंने किसानों की आवाज को पहुंचाया है।

इस अवसर पर संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अख्तर आलम, धरवेश कठेरिया, राजेश लेहकपुरे, संदीप वर्मा, जनसंपर्क अधिकारी बी. एस. मिरगे तथा छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

<u>बॉक्स में प्रकाशित करें</u> : मीडिया के छात्रों को किसानों की समस्याओं पर अध्ययन करने की सलाह देते हुए विजय जावंधिया ने कहा कि आप 15 एकड असिंचित जमीन धारण करने वाले कम से कम 10 हजार किसानों का चुनाव कर 3 साल में उसपर आयी लागत तथा जीवन जिने के लिए किसानों द्वारा किये गये खर्च का अध्ययन करें। इससे आपको किसानों की जमिनी समस्या का पता चल पाएगा। उन्होंने खुद से जुडी एक मिसाल देते हुए कहा कि में कृषि उत्पाद से आये पैसे से नहीं तो खेती बेचकर आये पैसे से ही कार खरीद पाया।

बी. एस. मिरगे, जनसंपर्क अधिकारी